भा.कृ.अनु.प.–भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान
ICAR-Indian Institute of Soybean Research
खंडवा रोड, इन्दौर–452001 (म.प्र.)
Khandwa Road, Indore-452001

फाइल नं. **F.No. :** तिलहन/विचार मंथन बैठक/प्रेस विज्ञप्ति/2020 दिनांक **Date: 25.09.2020**

भा.कृ.अनु.प. – भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान, इन्दौर में आयोजित तीन दिवसीय राष्ट्रीय तिलहन विचार मंथन बैठक एवं अनुसंधान–उद्योग–कृषक परिचर्चा के तृतीय एवं अंतिम दिन के अवसर पर आयोजित आज दिनांक 25 सितम्बर, 2020 को ''तिलहन उत्पादन तकनीकी के हस्तांतरण एवं अंगीकरण में चुनौतियाँ'' पर तकनीकी सत्र का आयोजन आनलाईन माध्यम से संस्थान की वेबसाईट तथा यू–ट्यूब चैनल पर सीधा प्रसारण किया गया। इस तकनीकी सत्र की अध्यक्षता डॉ. एस.के. मल्होत्रा, कृषि आयुक्त, भारत सरकार तथा सह–अध्यक्षता डॉ. एस.के. झा, सहायक महानिदेशक (तिलहल एवं दलहन), एवं डॉ. रणधीर सिंह, सहायक महानिदेशक (कृषि विस्तार) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली द्वारा की गई। इस तकनीकी सत्र में देश के विभिन्न क्षेत्रों से तिलहनी फसलों की तकनीकी के प्रचार–प्रसार से जुड़े विस्तार संस्थानों विशेषकर नौ कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थानों के निदेशक तथा निजी विस्तार संगठनों (सोपा, सॉलिडरिडेड, साल्वेंट एक्ट्रेक्शन्स एसोसिएशन) के अधिकारियों सहित लगभग 166 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। तकनीकी सत्र के प्रांरभ में भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान, इन्दौर की निदेशक डॉ. नीता खांडेकर ने सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया।

अपने अध्यक्षीय उद्‌बोधन में भारत सरकार के कृषि आयुक्त डॉ. एस.के. मल्होत्रा द्वारा इस वर्ष खरीफ 2020 के दौरान क्षेत्रफल में अभी तक की अधिकतम वृद्धि (12.1 लाख हेक्टेयर) होने की प्रारंभिक जानकारी दी गई। साथ ही उन्होंने केन्द्रीय स्तर पर भारत सरकार द्वारा चलायी जा रही नई योजनाओं विशेषकर क्षेत्रवार / जिलेवार तिलहन फसलों पर माइक्रो प्लानिंग तथा रबी के मौसम में तिलहनी फसलों को प्रचारित किये जाने की भी जानकारी दी।

इस तकनीकी सत्र के अवसर पर दो प्रमुख तकनीकी व्याख्यानों का आयोजन किया गया, प्रथम व्याख्यान ''खाद्य तेल कीं आत्मनिर्भरता में विस्तार कार्यकर्ताओं की भूमिका'' जिस पर डॉ. पी. चन्द्रशेखर, महानिदेशक, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, जयपुर ने अपनी प्रस्तुतीकरण के माध्यम से हाल ही में संसद द्वारा पारित बिल में किये गये ''कान्ट्रेक्ट फारमिंग'' की वर्तमान समय में उपयुक्तता बाबत अपने विचार प्रस्तुत किये। उनके अनुसार कान्ट्रेक्ट फारमिंग के अंतर्गत बनाये जाने वाले ''कृषक उत्पादक संगठन–एफ.पी.ओ.'' के माध्यम से कृषकों को मन मुताबिक कृषि फसल/उत्पाद की खेती, गुणवत्तायुक्त बीज/आदान की आवश्यक मात्रा, तथा प्राप्त उत्पाद के विपणन में स्वतंत्रता होगी। हाल ही में भारत सरकार द्वारा घोषणा किये गये कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर फण्ड के उपयोग से कान्ट्रेक्ट फारमिंग के अंतर्गत गठित किये जाने वाले ''कृषक उत्पादक संगठन–एफ.पी.ओ.'' के माध्यम से कृषि उत्पादन में वृद्धि होने उन्होंने आशा व्यक्त की।

इसी प्रकार राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के अध्यक्ष डॉ. चिंताला गोविंद राजूलू ने जानकारी दी कि वर्तमान में सम्पूर्ण देश में 8000 से अधिक ''कृषक उत्पादक संगठन–एफ.पी.ओ.'' कार्यरत है जिसमें अधिकतर संख्या में लघु एवं सीमांत कृषक सदस्य है। उनके अनुसार ''कृषि ऋण'' को भी एक आदान के रूप में माना जाना चाहिए। उन्होंने कृषकों के समूह / संगठनों को कान्ट्रेक्ट फारमिंग के अंतर्गत प्राप्त लाभों के दोहन हेतु जुड़ने का आव्हान किया।

तत्पश्चात् देश के विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थानों के निदेशकों द्वारा अपने–अपने क्षेत्रों में किये जा रहे तिलहन फसल उत्पादन तकनीकी के प्रचार–प्रसार कार्यक्रमों पर प्रस्तुतीकरण किये गये जिसमें डॉ. एस.आर.के. सिंह (जबलपुर), डॉ. रायुडू (बैंगलुरू), डॉ. एस.के. सिंह

(जोधपुर), डॉ. राजबीर सिंह (लुधियाना), डॉ. वाय.जी. प्रसाद (हैदराबाद), डॉ. अंजनी कुमार (पटना), डॉ. लाखन सिंह (पुणे), डॉ. बी.सी. डेका (बारापानी) एवं डॉ. ए.के. त्रिपाठी (गुवाहाटी) आदि ने इस तकनीकी सत्र के माध्यम से संबंधित क्षेत्रों में उपलब्ध धान–पड़त/पंजाब राज्य में धान–गेहूं फसल प्रणाली के अंतर्गत उपलब्ध भूमि पर तिलहनी फसलों के क्षेत्र में वृद्धि किये जाने की संभावना दर्शायी। इस दिशा में तकनीकी सत्र के अध्यक्ष डॉ. एस.के. मल्होत्रा जी ने कम उत्पादकता वाले क्षेत्रों को चिन्हित कर तकनीकी के प्रचार–प्रसार हेतु अतिरिक्त प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। इस अवसर पर डॉ. नीता खांडेकर, निदेशक, भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान ने तिलहनी फसलों की अत्यंत पुरानी किस्मों के डी–नोटिफिकेशन हेतु आवश्यक कार्यवाही का सुझाव प्रस्तुत किया जिससे नवीनतम प्रजातियों के प्रचार–प्रसार होने में आसानी हो सकें। इसी प्रकार कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थानों के सभी निदेशकों ने औपचारिक एवं अनौपचारिक बीज उत्पादन वितरण प्रणाली को प्रोत्साहत करने हेतु कार्य किये जाने की अनुशंसा की जिससे स्थान उपयुक्त कृषकों की पसंदीदा तिलहनी किस्मों के गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन एवं वितरण स्थानीय स्तर पर किया जा सकें।

तकनीकी सत्र के अध्यक्ष ने तिलहनी फसलों के प्रचार–प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले किस्मों के बदलाव हेतु कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थानों के सभी निदेशकों को सलाह दी। साथ ही पंजाब राज्य में धान–गेहूं फसल प्रणाली में विविधीकरण हेतु खरीफ के मौसम में सोयाबीन तथा रबी के मौसम में केनोला की फसल को लेने की प्रबल संभावना व्यक्त की। इसी प्रकार कुछ क्षेत्रों में जैसे कोटा, राजस्थान में सोयाबीन आधारित पनीर का उद्यम, मध्यप्रदेश के कृषकों द्वारा सोयाबीन बीज उत्पादन एवं विपणन पर उद्यम एवं पंजाब में तेल एक्स्ट्रेक्शन हेतु लघु प्रसंस्करण प्लांट जैसे क्षेत्रों में उद्यमिता विकास हेतु कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थानों द्वारा किये गये प्रयासों की सराहना की। इस अवसर पर सभी निदेशकों ने उनके संबंधित क्षेत्रों में उपयुक्त फसलों के साथ तिलहनी फसलों को अंतर्वर्तीय फसल के रूप में प्रवेश करने हेतु प्रयासों की जानकारी दी। शेष अन्य क्षेत्रों में उपयुक्तता अनुसार राम तिल एवं तिल्ली के उत्पादन हेतु विशेष प्रोत्साहन योजना शुरू किये जाने की सलाह दी।

इस अवसर पर साल्वेन्ट एक्स्ट्रेक्टर्स एसोसिएशन के डॉ. हरीश व्यास द्वारा अरण्डी बीज उत्पादन के आदर्श मॉडल की सफलता गाथा प्रस्तुत की जिससे गुजरात एवं राजस्थान के 15000 से अधिक कृषक लाभान्वित हुए। उनके अनुसार तिलहनी फसलों में उत्पादन क्षमता की स्थिरता को देखते हुए कृषकगण धीरे–धीरे तिलहनी फसलों से उदासीन होते गये। उन्होंने यह भी कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य दीर्घकाल के लिए प्रभावी नहीं है जबकि उत्पादकता में वृद्धि दीर्घकालीन समाधान है।

दि सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोएिशन ऑफ इंडिया, इन्दौर के श्री डी.एन. पाठक ने वर्तमान तिलहनी फसलों की समीक्षा करते हुए कम उत्पादकता हेतु राज्य सरकार द्वारा संचालित कृषि विस्तार प्रणाली की निंदा की जिसने कृषि तकनीकी / ज्ञान को कृषकों तक पहुंचाने में संतोषजनक कार्य नहीं किया। कृषि तकनीकी के प्रचार–प्रसार संबंधी अन्य निजी संस्था सॉलिडरिडेड के डॉ. सुरेश मोटवानी द्वारा उनकी संस्था द्वारा इस अवसर पर जनभागीदारी आधारित क्रियान्वित विस्तार कार्यक्रमों की जानकारी दी तथा बदलते हुए मौसम के परिप्रेक्ष्य में हाल ही में प्रारंभ किये जा रहे ''वोडाफोन–आइडिया सॉलिडरिडेड प्रोग्राम'' की जानकारी दी।

तकनीकी सत्र के अंत में अध्यक्ष एवं सह–अध्यक्षों द्वारा तिलहनी फसलों के उत्पादन में वृद्धि हेतु जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए उन्नत गुणधर्मो वाली किस्मों के विकास किये जाने की अनुशंसा की। साथ ही उन्होंने बदलते हुए जलवायु की स्थिति में श्रेष्ठतम उत्पादन पद्धतियाँ, जैविक तिलहन उत्पादन प्रोटोकॉल आदि के प्रचार–प्रसार करने हेतु सभी के सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया।

इस तकनीकी सत्र के आयोजन में भारतीय सोयाबीन अनुसंधान अनुसंधान के डॉ. बी.यू. दुपारे तथा डॉ. महाराज सिंह ने अपनी भूमिका निभाई।